CALLING ATTENTION TO MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

Situation arising out of the unprecedented rise in the price of paper

श्री जगदीश प्रसाद माथुर: (उत्तर प्रदेश-उपसभापति महोदया, में आपकी अनुमति से कागज के मूल्यों में अप्रत्याशित वृद्धि से उत्पन्न स्थिति की ओर उद्योग मंत्री का ध्यान दिलाता हूं।

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री और उद्योग मंत्रालय भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : उपसभापति महोदया मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहुंगी कि पेपर की बढ़ती हुई कीमतों के संबंध में व्यक्त की जा रही चिन्ता से सरकार पूणत: अवगत है। पेपर उद्योग से संबंधित विभिन्न पक्षों से लगातार बातचीत की जा रही है ताकि समस्या का सही आँकलन करते हुए सुधारात्मक कार्रवाई की संभावनाओं पर विचार किया जा सके।

अभी पेपर एवं न्यूजप्रिंट के मूल्य एवं वितरण पर कोई नियंत्रण नहीं है। जहां तक न्यूजप्रिंट का प्रश्न है कुल मांग के 50 प्रतिशत की आवश्यकता देश के उत्पादन से पूरा किया जाता है। सामान्य प्रकार के कागज में देश आत्मनिर्भर है। देश की पूरी आवश्यकता का मात्र दो प्रतिशत कागज ही आयात किया जाता है। यह आयात भी मात्र कुछ विशेष प्रकार के कागजों जैसे–चेक पेपर, सिक्योरिटी पेपर, फिल्टर पेपर इत्यादि तक ही सीमित है।

यह जानकर खुशी होगी कि देश में पेपर एवं न्यूजप्रिंट के उत्पादन में निरन्तर वृद्धि हो रही है। 1991 में जहां 19.65 लाख टन पेपर का उत्पादन होता था वह गत 4 वर्षों में बढ़ते हुए अब 1994–95 में 22 लाख टन हो गया है। न्यूजप्रिंट का उत्पादन 1991–92 के 2.89 लाख टन से बढ़कर 1994–95 में 3.8 लाख टन हो गया है।

पेपर उत्पादन करने वाली 350 मिलें कार्यरत हैं जिनकी क्षमता 58 लाख टन की है। 60 लाख टन अतिरिक्त क्षमता के शीघ्र ही सृजन की आशा है। न्यूजप्रिंट की वर्तमान उत्पादन क्षमता 5.5 लाख टन की है। दाखिल किये गए आई० ई० एमस० एवं निर्गत किये गए एल. ओ. आईज के अनुसार 20 लाख टन अतिरिक्त क्षमता के सृजन की आशा है।

हाल ही राइटिंग एवं प्रिंटिंग पेपर की दरों में हुई वृद्धि की ओर सरकार ने ध्यान दिया है। कोयला, कॉस्टिक सोडा, बिजली, पल्प, रद्दी कागज इत्यादि जैसे इम्पुट्स की दरों में अप्रत्याशित वृद्धि के कारण ही न्यूजप्रिंट, राइटिंग एंव प्रिंटिंग पेपर की दरों में वृद्धि हुई है। आयातित न्यूजप्रिंट की दरों में अप्रत्याशित वृद्धि ही इस समस्या का मूल कारण है।

गत वर्ष 440 यू. एस. डालर प्रति मीट्रिक टन की दर से बढ़कर अब इस वर्ष न्यूजप्रिंट की दर एक हजार यू. एस. डालर प्रति मीट्रिक टन हो गया है। गत वर्ष तक देश में उत्पादित न्यूजप्रिंट की तुलना में आयातित न्यूजप्रिंट 3 हजार रुपये से 4 हजार रुपये तक सस्ता था। परन्तु अब वह देशी न्यूजप्रिंट से 3 हजार से 4 हजार रुपये तक महंगा बिक रहा है। इन परिस्थितियों में देशी न्यूजप्रिंट की मांग बहुत बढ गई है एवं इसकी कमी महसूस की जा रही है। इस कमी के कारण राईटिंग एवं प्रिंटिंग पेपर का प्रयोग समाचार पत्रों के लिए भी किया जा रहा है।

आप अवगत होंगे कि कल ही न्यूजप्रिंट की नई आयात नीति की घोषणा की गई है। आशा है कि इस नई नीति के फलस्वरूप न्यूजप्रिंट की कमी को पूरा किया जा सकेगा एवं राईटिंग तथा प्रिंटिंग पेपर की उपलब्धता भी बढ़ेगी।

पाठ्य-पुस्तक एवं नोट-बुक की छपाई में महसूस की जा रही कठिनाइयों के निराकरण के लिए भी सरकार सजग है। शिक्षा क्षेत्र में पेपर की आवश्यकता का आकलन किया जा रहा है। इसके बाद पाठ्य-पुस्तक एवं नोट-बुक छपाई में हो रही कठिनाइयों के निराकरण के लिए कार्यवाई की जायेगी।

पेपर की अपर्याप्त आपूर्ति एवं दर में वृद्धि की समस्याओं से सरकार पूर्णत: अवगत है एवं इसकी कमी को दूर करने के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं :–

1. वेस्ट लैण्ड एवं डीग्रेडेड फॉरेस्ट लैण्ड को विकसित कर इंडस्ट्रियल प्लान्टेशन लगाने पर

सरकार विचार कर रही है ताकि कच्चे-माल की कमी को पूरा किया जा सके ।

2. वुड पल्प एवं रद्दी कागज का आयात बगैर लाइसेंस के किया जा सकता है और इस पर कस्टम डयूटी भी काफी कम कर दी गई है ;

3. विशिष्ट प्रकार के पेपरों जिनका उत्पादन पर्याप्त मात्रा में देश में नहीं होता है उन पर लगने वाले अधिकतम आयात शुल्क को 65 प्रतिशत से घटाकर 40 प्रतिशत इस वर्ष के बजट में कर दिया गया है ।

4. एग्रीकल्चरल रेसीड्यूज, बगास एवं अन्य गैर-परम्परागत रॉ मैटीरियल के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उन पेपर मिलों को लाइसेंसिंग की शर्तों से मुक्त कर दिया गया है जो कम-स-कम 75 प्रतिशत तक पल्प इन रॉ मैटीरियल से प्राप्त करते हैं ।

5. राइटिंग एवं प्रिंटिंग पेपर, जिनमें कम से कम 75 प्रतिशत पल्प गैर-परम्परागत रॉ मटीरियल से प्राप्त है उसमें मात्र 5 प्रतिशत उत्पादन शुल्क लगता है ।

6. सेन्ट्रल पल्प एवं पेपर रिसर्च इन्स्टीट्यूट, सहारनपुर को पेपर उद्योग के विकास से संबंधित विभिन्न अनुसंधान कार्यक्रमों में लगाया गया है ।

अन्त में मैं सभी माननीय सदस्यों को पुनः आश्वस्त करना चाहूंगी कि राइटिंग एवं प्रिंटिंग पेपर की बढ़ी हुई दरों एवं उससे हुई कठिनाइयों से सरकार पूर्ण रूपेण अवगत है । साथ ही पर्याप्त मात्रा में तथा उचित दर पर पेपर उपलब्ध कराने के लिए सरकार काफी प्रयत्नशील भी है । सरकार द्वारा उठाये गये विभिन्न कदमों का उद्देश्य उत्पादकता बढाना, कच्चे-माल को अधिक उपलब्ध कराना एवं बिक्री दर घटाना है । समय-समय पर सरकार पेपर उद्योग से संबंधित व्यक्तियों से वार्ता कर उन्हें प्रभावित करने का प्रयास कर रही है कि पर्याप्त मात्रा में उचित दर पर कागज उपलब्ध करायें । हमें यह विश्वास है कि सरकार द्वारा की गई विभिन्न कार्रवाइयों से आने वाले दिनों में स्थिति में काफी सुधार होगा ।

उपसभापति : माथुर साहब आप बोले, इसके पहले मैं जरा हाऊस में अनाऊंस कर दूं ;

Mathur Saheb has agreed that he would make a brief statement on it. We have to finish it by 1.30 p.m.

डेढ़ बजे हमें यह कालिंग अटेंशन खत्म करना है क्योंकि ढाई बजे से हमको प्रेजीडट के मोशन आफ थैक्स को लेना है ।

We cannot delay that.

इसलिए कृपा करके सवाल पूछें भाषण न करें ।

Please put pointed Questions. This is the basic rule for a Calling Attention Motion. If everybody co-operates, then I am sure that we can accommodate many more Calling Attention Motions every week, at least once every week. It will be to the benefit of the House if we abide by this procedure and have more Calling Attention Motions.

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : महोदया, मैंने मंत्राणी जी का वक्तव्य सुना । ज्यादातर उन्होंने न्यूजप्रिंट को बात कही हैं । बाकी कागजों के बारे में उन्होंने केवल कुछ तथ्य सामने रखे हैं । वास्तव में क्या कर रहे हैं, यह कुछ नहीं बताया है । इस बात पर तो मैं संतोष प्रकट करता हूं, बधाई तो नहीं देता कि न्यूजप्रिंट के बारे में कल कुछ एलानात किये लेकिन समाचार पत्र वाले तो अर्गनाइज्ड सेक्टर हैं प्रभावी लोग हैं वे आप पर दबाव डाल सकते हैं और उसका लाभ भी हुआ है असर भी हुआ है । लेकिन यहां पर बहुत बड़ा तबका ऐसा है विद्यार्थियों का है, साहित्यकारों का है, वैज्ञानिकों का है, उनको प्रभावित करने वाले जो कागज हैं, उसके बारे में आपने कोई भी आश्वासन नहीं दिया है । तो सब से पहला प्रश्न मेरा यह है कि सरकार कहती है कि हम बड़े चिन्तित हैं, बड़े अवगत हैं, प्रयत्न कर रहे हैं लेकिन यह बताइये कि क्या कर रहे हैं ?

चिंता व्यक्त करना, अवगत होना, बेईमानी है जब तक कि आप ठोस बात न कहें जैसे कि ठोस बात आपने न्यूज प्रिंट के बारे में कही है । दूसरा आपने जो कोटों का अंदाजा बताया है वह क्या है ? मैं आप से पूछना चाहता

हूं कि गत तीन साल में कितनी कीमतें बढ़ी हैं ? मेरी जानकारी के अनुसार केवल गत तीन महीनों के अंदर कम से कम 1988 से लेकर 120 प्रतिशत कीमतें बढ़ी हैं । अच्छा कागज जिसे क्रीम लोड कहते हैं वह 34–35 हजार पर टन की तुलना में 1991 में 14,000 रुपए था । इसकी कीमतें क्यों बढ़ी हैं । यह पूछना चाहूंगा । उसके बाद इम्पोर्ट ड्यूटी 98 परसेंट अभी भी है । आपने उसको घटाकर, गलत कहा हैं कि न्यायोचित किया है । आज भी इम्पोर्ट ड्यूटी वाकई जो अच्छा कागज है उस पर 98 प्रतिशत है । क्या आप उसको घटाएंगे ? कितना घटाएंगे ?

दूसरा इम्पोर्ट आफ पल्प । बात सही है । पल्प इम्पोर्ट क्यों हो रहा है । ज्यादा से ज्यादा, अधिकांश रद्दी कागज के जो पल्प हैं उससे बनते हुए कागज का लोग इम्पोर्ट कर रहे हैं । जो पेड़ का कागज है, जो वुड से, जंगल से बनता है उसकी संख्या घट रही हैं और अब आपने यह कहा है, हां हम जंगल लगाने की बात कर रहे हैं । तो मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि जंगल लगाने की आपकी योजना का विस्तार से वर्णन करें । उसके साथ ही, क्या सरकार ही लगाएगी या प्रायवेट कम्पनियां जो हैं उनको भी आप ही प्लांटेशन के लिए एरिया और समय देंगे ? मेरी जानकारी में है कि कुछ जगहों पर दिया हुआ है । तो कितना एरिया बढ़ाएंगे अगला सवाल यह है । आपने कहा है कि इतनी खपत है, इतनी आश्वकता हैं । क्या अगल सालों में अंदाजन दो हजार साल तक हमारी कितनी आवश्यकता होगी ? आज जो इस समय है, नार्मली वैसे तो लाखों में बताया गया है लेकिन 2.25 मिलियन टन खपत आज मामूली तौर पर है । जो इस कागज से संबंधित हैं उनका अंदाज यह है कि यह मांग अगले सालों में दो हजार ईसवी से लेकर 5 मिलयन टन प्रति वर्ष हो जाएगी इसको पूर्ति के लिए आप क्या करना चाहते हैं । आज कैपेसिटी आपने बतायी हैं कि 3.5 मिलियन टन पर इयर हमारे 350 कारखानों की है । लेकिन वे अण्डर यूटिलाइज्ड हैं । 3.5 मिलियन टन के बजाय आज केवल 2.9 मिलियन टन कागज ही बनाया जा रहा है । कारण क्या है, उनके पास जो सामग्री हैं वह उपलब्ध नहीं है, उनको पल्प मिलता नहीं है । जगल काटकर लेते नहीं ।

तीसरी बात यह है जैसे आपने शक्कर के बगास की बात की । बगास का मतलब यह है जो ये कहते हैं छिलका वगैरह है इससे जो कागज बनता है वह। उसके ऊपर पहले छूट थी । गत बजट में आपने 5 प्रतिशत इस पर ड्यूटी लगा दी । 5 प्रतिशत ड्यूटी लगाने के बाद आप इस कागज की कीमत को जो और दूसरे कागज हैं उनके बराबर ले आए । इसलिए प्रोडक्शन के लिए जो आप उत्साहित करना चाहते थे वह उत्साह नहीं मिल रहा है इससे, बल्कि और उल्टा असर पड़ रहा है । मेरा आपसे निवेदन यह हैं कि जो बगास से कागज बनाने के कारखाने हैं उनकी गलती नहीं हैं, यह बात ठीक है । आज से 5–7 साल पहले बगास से बने हुए कागज की जो क्वालिटी थी वह अच्छी नहीं होती थी । आज उन्होंने क्वालिटी को बढ़ाकर अच्छा कर लिया है तो इस कसूर में आपने उनको दाण्डित कर लिया है । गलत है । आज हमारे यहां बहुत बड़ी संख्या में शक्कर के कारखाने हैं जिनका कि बगास बनता है, उसका उपयोग आपने घटाया है । मेरा कहना है कि आपने बहुत खुशी से कह दिया कि बहुत कम टैक्स लगा है लेकिन आपने 5 परसेंट ड्यूटी बढ़ा रखी हैं । इसके साथ ही एक और जुड़ा सवाल है कि जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं शायद आपने ध्यान नहीं दिया, जो कागज बनाने की कला के लिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हिंदुस्तान में हैं उनकी क्या हालत है । उनकी ओर भी आप को ध्यान देना पड़ेगा । हमारे लोगों की जानकारी के अनुसार या जो कागज उद्योग से संबंधित है उनकी जानकारी के अनुसार जितने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं सब पुराने पड़ गए हैं । जो लेटेस्ट टेक्नालाजी है उनके इक्विपमेंट के साथ सिखाने की कोई व्यवस्था नहीं है । यदि आप चाहते हैं कि कागज का उत्पादन बढ़े, इम्पोर्ट कम हो और अगर हमारी खपत पूरी हो जाती हैं तो हम एक्सपोर्ट भी करें तो इसके लिए आपको ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के विषय में ध्यान देना पड़ेगा ।

आखिरी सवाल पूछ कर मैं समाप्त करूंगा क्योंकि मैडम ने मुझसे वायदा लिया है कि मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा । आखिरी सवाल, जिस प्रकार से न्यूज पेपर्स के, जो अखबार के लोगों ने हड़ताल की वैसे ही जो कागज से संबंधित

कारखानेदार हैं, कागज से संबंधित व्यापारी हैं उन्होंने भी ज्वांइट एक्शन कमेटी बनाई है और उन्होंने सरकार को मैमोरेंडम भी दिया है तो मैं पूछना चाहूंगा कि उनकी मांगे क्या-क्या हैं ? मेरी मोटी-मोटी जानकारी में तो उन लोगों की दो-तीन मांगे हैं : इंपोर्ट ड्यूटी, विदड्राल आफ एक्साइज ड्यूटी ड्यूटी कम की जाए और खास तौर स प्लांटेशन की जो व्यवस्था है री-प्लांटेशन करना चाहिए जिससे आपने डी-ग्रेडेड लैंड के लिए कहा है। आपने कहा है कि उसमें यह प्राइवेट लोगों को दिया जाए । मेरे चार-पांच सवाल है इनका आप जवाब देने की कृपा करें । धन्यवाद ।

SHRI SANATAN BISI (Orissa): Madam, so far as the statement given by the Minister is concerned, I have only three questions. First, the statement is silent as far as corrective measures to protect the indigenous industry are concerned. Secondly, permission should be granted for mere production. Thirty there is no assurance regarding small newspapers, including the regional newspapers. These are the only three questions.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Very good. I hope everybody will take a cue from this. Thank you very much.

बिसि साहब, आप रोज बोला कीजिए और आपकी पार्टी की तरफ से इतना बोलिए ।

Yes, Mr. Virumbi. Take a cue from Mr. Bisi. Mr. Gurudas Das Gupta, you too, please.

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI (Tamil Nadu): Madam, as far as this price increase of newsprint is concerned, I also want to say only a few words.

Even though the OGL policy is welcome, I want to know what the remedy is for the medium and small newspapers. Financial aid through banks to small and medium newspapers is essential since they cannot pay huge amounts for importtng the newsprint. The Government should come forward to help them by instructing the State Trading Corporation to procure newsprint and stock it so that the small and medium newspapers can purchase it from the STC. I want to know whether the Government will come forward to instruct the STC to procure the newsprint and stock it so that the small and medium newspapers can purchase it from there.

There is another point, Madam. The price of the newsprint has tncreased by 50 per cent within the last four months. It is unprecedented in the history of India. It is one of the consequences of the liberalisation policy that was adopted.

The printing of notebooks for school children has also been very much affected by this price tncrease because the printers have to obtain the supply order after having tendered the quotation based on the prices prevailing at the time of submitting the quotations. Most of the printers are suffering heavy losses due to this unprecendented rise in the prtces of paper. I want to know what proposal the Government has to supply paper to printers of notebooks meant for school children, so that they do not suffer losses due to fluctuations in the prices of paper. Otherwise, it would affect the studies of children also. How are you going to reduce this unprecedented increase in the prices? Will the Government appoint a committee to study the cost structure of these mills? It ts very important Madam. Will the Government appoint a committee to study the cost structure of these mills so that they may not increase the prices at their will and pleasure?

Apart from this, in this statement you have given the production capacity of these 350 mills as 38 lakh tonnes. In 1990-91, it was 19.65 lakh tonnes and in 1994-95 it was 22 lakhs tonnes.

To increase thetr capacity further what are the actions the Government propose to take? Madam, as far as production of newsprint is concerned, they say that 3.80 lakh tonnes is being produced at present. Their capacity is 5.50 lakh tonnes, i.e., five lakhs and fifty thousand tonnes. From the statement what I find is that this 3.80 lakh tonnes is going to cater to the needs of about 50 per cent of newsprint demand. Therefore, I can infer from the statement-that the ootal demand of newsprint tn India

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: is 7.60 i.e., seven lakhs and sixty thousand tonnes out of that your capacity, as you have stated, is 550 thousand tonnes. You have said that you are expecting to increase the production to 20 lakh tonnes, but there is no explanation how you are going to increase it. You have only said that the letter of intent has been issued. I want a concrete answer from you as to how you are gotng to increase it from 550 thousand tonnes to the present demand of 760 thousand tonnes. This is one of the important issues. Apart from that, due to this price increase the prices of newspapers have also increase, tariff on advertisements is going to increase and ultimately the common man who buys the newspaper as well as the small newspapers are going to suffer a lot. I hope, the Government will take some proper action tn this regard. I want a definite answer from the hon. Minister about he Committee that they are going to appoint and how they are going to increase the production of newsprint. With these words, I conclude.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Everybody take a cue Bisiji is the leader today.

SHRI JAGESH DESAI (Maharashtra): Madam Deputy Chairperson, first of all, I would like to draw the attentton of the Minister to the increasing prices of newsprint and paper. Unfortunately, the paper industry is squeezing both the newspaper industry and the common students who have to buy paper at very high prices. I am giving you only two examples. For all commodities the price rtse in the year 1991-92 was 13.7 per cent only whereas the increase in the prices of newsprint and paper whopped up by 24.5 per cent. Similarly, in the year 1992-93, the all-commodities price-rise was only 10 per cent whereas the price rise of newsprint and paper was 36 per cent. What do they want? The industry wants to squeeze the people. They want to make money. In the month of October, 1994, the newsprint prtce increased by Rs. 1,500 per tonne and after two months, i.e. in the month of December, again it was increased by Rs. 1,500. The Minister should examine whether in these two months the cost of production had gone up to such an extent that they increased the price by Rs. 1,500 per tonne. Madam, there is nothing; there is short supply of paper. This industry wants to make money at the cost of consumers of paper and also at the cost of those who read newspapers and those who go to schools and colleges. These people have to pay a very high price.

Madam, I am a member of the Central Consumer Council. We had a meeting of this Council a month ago and at that time a Working Group had gone into the price structure of not only paper but also all the commodities. This Group found that the industry was squeezing the consumers. Therefore, it suggested for a Price Monitoring Commission. Unfortunately, Madam, the industrialists who were members of that Committee, opposed it. This shows that the industry does not want to help consumers. They only want to squeeze them. As such, I would like to know from the Minister why this price rise has been done recently. It should be found out as to what the cost of production is and what the fair profit margin is. After that, if the cost of production has gone up allow them to that extent a fair profit margin. Otherwise, now, I think, this House and the people of this country will not tolerate this kind of a squeeze of consumers in the naem of liberalisation. If they want to squeeze the people and the consumers, then we have to have monitoring of the prices. I think, the time has come when you have to see that the moritoring of the prices is done. Otherwise, the newspaper industry, more so the smaller newspapers whose cost of production is very high because of the less number of copies sold, will have to close down their establishments. As such, the Minister should take immediate action and must tell us

whether the Government will think of having a price monitoring commission, not only for newsprint and paper, but also for the other mass consumption commodities which the people require. At least, for paper, let us know, will you do it or not?

THE DEPUTY CHAIRMAN: Shri P. Upendra; not here. Shri Gurudas Das Gupta.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA (West Bengal): Madam, I am sorry to say that the statement the hon. Minister has presented before us is schoolboyish because it narrates the problems which are known to everybody. It hold out for future a programme, a common programme, and there is no sense of urgency. This statement could have been produced by any member of the Indian bureaucracy one year back or two years back. There is nothing new in it. It does not also seek to go into the root of the problem.

The point is, in our country, ignorance is cheap and knowledge is costly. Ignorance is cheap because of Government's failure to make adequate investments in the social sector. Knowledge is costly because there is a constant and speculative rise in the prices of paper. The prices are increasing, totally unrelated to the cost. It is speculative in nature and there is no sence of urgency on the part of the Government. At least, the statement does not indicate whether it is going to curb the price rise or not. In fact, on page 2 of the statement, the Minister justifies the increase in prices! She is saying that on account of the unprecedented increase in the cost of inputs like coal, caustic soda, electricity and waste paper, the cost of newsprint and writing paper has increased. How does she know that because of the increase in the prices of these commodities the increase in the price of paper is justified to this extent? If the hon. Minister makes such a statement, this is absolutely going to be an inducement for the speculators.

Secondly, the Government does not indicate its responsibility to curb the price rise of paper. It has a social responsibility. The Government must tell that it has a social obligation to ensure that the price of paper does not increase the way it is increasing at the moment. The Government does not indicate its social obligation. It is just like any other commodity just like meat, soap, detergents or anything like that. It is essential. It is essential because the largest number of illiterates in the whole world are living in India and you cannot deal with the problem of illiteracy if the price of paper is allowed to rise in a speculative way. There is a question of social awareness. She does not indicate that. Therefore, Madam, I would like the hon. Minister to tell us whether the Government is under obligation to see that the price of paper does not increase, at least, much beyond is warranted. There should be some sort of a control. It is not because of the increase in the prices of the ingredients. The Government must say that it will come down heavily on the unwarranted price rise of paper. The Government must say that since it is most useful for social advance, it is its obligation to ensure that.

Secondly, there has been an unprecedented rise in the price of paper and since I believe the Government will take some measures to control this speculation in the paper trade, the Government must also consider the question of giving subsidy. The subsidy cannot be discussed only in an abstract way. The subsidy should not be discussed just as a subsidy to any commercial venture. No. It is a subsidy to fight illiteracy, it is a subsidy for the national advance. Government must consider that at least up to the point when the national production does not reach the necessary level.

Shri Gurudas Das Gupta:

Thirdly, I must say that the paper industry is being run inefficiently. We started speaking in terms of jargon, modernisation, high technology, etc That is the second stage. What about running efficiently the existing production units? If the existing production units are run efficiently, then we can increase the production. We should ensure that the closed paper mills are opened. There are a number of paper mills in the country which are closed. The Government should ensure that these mills are opened. There should be some kind of an urgency. Therefore, the Government must discuss to ensure that these mills, whether private or public, are run efficiently, that the closed mills are opened and bank credit is made available to them. This is where this question should be linked with the social obligation. There should be an easy supply of bank credit.

Madam, in India we are having enough raw material, we are having enough raw material to produce paper. This is also a modern fashion to put the items on the OGL as if by importing high cost paper, we can tackle the problem. It is not a question of newsprint alone. It is a question of producing cheap textbooks. Therefore, it is not by putting items on the OGL that we can settle the problem. The production has to be increased, exitsing mills should be run efficiently, subsidy has to be arranged and in order to increase the production when the country is having enough raw material, steps should immediately be taken. It should not be a 20-year plan. The Government must tell as to what the short term programme is, instead of saying, "We are importing." If you are importing, the cost will rise and the nation will suffer because you will have to reduce the tax. That is one of the main problems; that is not the only problem. Let us get out of the present modality, let us think in ter of augmenting our national production. What is your programme for that? Let the Government tell the people that this is is programme. While saying so, Madam, I ask the hon. Minister to tell the country, to tell the Parliament that this is its programme, this is the Government's programme, short-term programme, that it is going to curb speculation, it is going to increase production, that it is going to ensure a smooth and efficient running of the paper mills and it is going to ensure that there will be subsidy. You must first of all, say that it is one of your basic social obligations to make the availability of paper at cheap cost so that the massive national problem of illiteracy can be properly tackled. Thank you. Madam.

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभापति जी, जो अखबारी कागज़ और बच्चों के लिखने-पढ़ने की किताबें और कापियां है और साथ-साथ जो अन्य प्रकार के कागज़ हैं, सभी की कीमतों में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई और इनका जो कुप्रभाव है, न केवल बड़े समाचार-पत्रों पर पड़ा है बल्कि छोटे समाचार-पत्र भी ऐसे अखबार जो गांवों में जाते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं, लघु समाचार-पत्र और बच्चों की जो कापियां और किताबें हैं, उन पर भी पड़ा है और इनका हाल यह है कि मंत्री जी ने इस बात को महसूस किया है । जहां तक अखबारी कागज़ का प्रश्न है, कुल मांग की पचास प्रतिशत आवश्यकता देश के उत्पादन से पूरी होती है और सामान्य प्रकार के कागज़ पर हम आत्मनिर्भर हैं लेकिन पिछले छह माह में अखबारी कागज़ की जो कीमत है, वह प्रति मीट्रिक टन जो 18650 रुपए थी, वह इस समय बढ़ कर 27300 रुपए हो गई है यानि करीब-करीब 46 प्रतिशत की उसमें वृद्धि हुई है और इसी प्रकार से लिखने-पढ़ने के कागज़ हैं, दिसम्बर, 94 में जिस कागज़ की कीमत एक रिम की, जिसका वजन होता है 18.6 किलोग्राम, 375 रुपए थी,

वह बढ़ कर करीब आज से पंद्रह दिन पहले साढ़े सात सौ हो गयी थी यानि दुगुनी वृद्धि हो गई और पंद्रह दिन में और हो गई होगी। तो इससे सभी को परेशानी है और मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में इस बात को कहा हैं कि उस पर वे ध्यान दे रहे हैं, निराकरण कर रहे हैं लेकिन निराकरण करने के लिए कागज के दाम जो बढ़ गए हैं, इनको घटाने के लिए क्या उपाय सरकार करने जा रही है, मेरा एक तो यह प्रश्न है ।

दूसरे जो उत्पादन कर है या जो ऐक्साइज हैं, इनमें कमी करने का कोई इरादा सरकार का है या नहीं हैं और साथ ही साथ सेल्स टैक्स भी ? सेल्स टैक्स प्रदेश की सरकारें भी लगाती हैं तो सेल्स टैक्स के कारण भी कागज की कीमतों में वृद्धि हो रही है। तो बिक्री कर की वृद्धि करने के सिलसिले में सरकार का क्या इरादा है ? और एक मांग यह हैं कि यह जो आयात शुल्क हैं, आयात शुल्क से इन कागजों को पूरी मुक्ति दे दी जाए और गुरुदास दासगुप्त जी ने अभी ध्यान आकर्षित किया कि कागज के संबंध में जो सबसिडी हैं, रियायती मूल्य पर भी कागज कम से कम जो बच्चों के लिए किताबें हैं, कापियां हैं, अन्य प्रकार का जो सुरुचिपूर्ण साहित्य हैं, उसके लिए रियायती दर पर कागज उपलब्ध कराया जाए । इस सिलसिले में सरकार क्या कदम उठाएगी ?

जो रेल बजट प्रस्तुत किया गया, इसमें भी रेल भाड़े में वृद्धि की गई और उस बढ़ोत्तरी ने भी कागज की कीमतों को बढ़ाने का काम किया है। तो इस सिलसिले में भी सरकार का कोई कारगर कदम उठाने का इरादा हैं या नहीं क्योंकि हमारे संविधान में दिया हुआ हैं कि सबके लिए शिक्षा मिलनी चाहिए, 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा है और सबके लिए शिक्षा सरकार की पालिसी हैं, सारे देश की नीति हैं और इसलिए अगर कागज के दाम बढ़ेंगे, बच्चों की कापियों, की कीमतें बढ़ेगी तो उससे शिक्षा ही महंगी होगी, कम से कम गरीब लोगों को शिक्षा तो मिल नहीं सकेगी, इसलिए मेरे तीन-चार प्रश्न हैं और इनका उत्तर देने की कृपा करें।

श्री जनेश्वर मिश्र (उत्तर प्रदेश) : उपसभापति महोदया, सबसे पहले मैं एक शिकायत कर दूं कि आज के दो-तीन दिन पहले हम लोगों ने इस सवाल को जब उठाया था तो आज की तारीख, जो 27 तारीख है, देश के अखबार वालों ते आज हड़ताल करने का नोटिस दिया था। हम लोग उम्मीद करते थे कि इस सदन मे में 27 के पहले कागज पर बहस कर लेंगे लेकिन बगल के सदन में एक दिन पहले दहस्त हो गई । वहां पर सरकार ने कुछ आश्वासन दे दिया और आज इस मुद्दे की जो गरमी कल तक थी, थोड़ी ठंडी पड़ गई है । यह मैं अपनी शिकायत करूंगा । अपने सदन में भी मुद्दे की गरमी उतनी ही रहनी चाहिए थी जितनी कि बगल के सदन में थी । कागज का संकट, फिर मैं दोहराना चाहता हूं, केवल इसलिए नहीं हैं कि हमारे यहां कागज के उद्योग में इस्तेमाल होने वाली चीजें या रेल भाड़े वगैरह में वृद्धि की गई हैं, उनके दामों में वृद्धि हो गई है। माननीय मंत्री जी ने जो बयान दिया, उसको मैं पढ़ रहा था तो उससे ऐसा लग रहा था कि एक बार भी चार महीने में, छह महीने में जिस रफ्तार के दाम बढ़े हैं कागज के, यह बहुत भयानक है । उस रफ्तार से न कोयले का दाम बढ़ा हैं, न रेल का भाड़ा बढ़ा हैं, न कास्टिक सोडा का दाम बढ़ा है उस रफ्तार से जिस रफ्तार से कागज के दाम बढ़े हैं। आज जो कागज उद्योग हमारा संकट में पड़ा है, उसका एक प्रमुख कारण हैं कि दुनिया के वे लोग जो कागज का इस्तेमाल करते हैं, हिंदुस्तान की नई आर्थिक और औद्योगिक नीति के चलते जो वर्तमान सरकार ने लागू की हैं, उनकी निगाह भारत के कागज पर गई है। वे यह जानते हैं कि कागज पैदा करने के लिए और मैं चाहता हूं कि मंत्री जी इस बात पर अपनी सफाई दें, अपने देश के कारखानों को अगर वे ठीक से चलाते हैं तो उनको यहां बहुत से जंगल काटने पड़ेंगे और पर्यावरण का

सवाल खड़ा हो जाएगा। भारत इसके लिए सबसे उपयुक्त स्थान माना जाता है मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा है कि हम नये-नये जंगलात बनाना चाहते हैं। नये जंगलात लगाने के बाद और पेड़ के तैयार होने तक कागज का दाम किस सीमा तक बढ़ जायेगा इसका मंत्री जी ने कोई आश्वासन नहीं दिया है। लेकिन उसके बाद वह पेड़ उसी रफ्तार से कटते रहेंगे और हमारे यहां से कागज विदेशों में निर्यात होता रहेगा तो यह निर्यात के साथ मजाक है। किसी जमाने में हिन्दुस्तान में कागज दुनिया में सबसे सस्ता माना जाता था और आज जिस तरह से कागज का निर्यात हो रहा है उससे दाम सस्ता होने की बात नहीं है पंडित नेहरू के जमाने से लेकर आज तक कभी भी कागज के दाम इस तरह से नहीं बढ़े। क्योंकि लोग मानते थे देश के बच्चों को इसकी आवश्यकता है। नेहरू जी के जमाने में कागज डेढ़ रुपए किलो बिका करता था और आज 40 रुपए किलो बिकता है।

उपसभापति : उस जमाने में लोग किताब पढ़ते थे और आजकल टी.वी. देखते हैं।

श्री जनेश्वर मिश्र : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्री जी इस बात का सफाई से जवाब दें कि कागज का निर्यात जो विदेशों में हो रहा है उससे हिन्दुस्तान के जो कागज के कारखानेदार हैं उनमें मनाफाखोरी की प्रवृत्ति बढ़ रही है, वे कागज को महंगा कर रहे हैं क्योंकि विदेशों से उनको ज्यादा पैसा मिलता है। सरकार विदेशी मुद्रा की लालची है इसलिए वह कागज से विदेशी मुद्रा कमाना चाहती है। बहुत सी चीजों का निर्यात कर देना चाहती है। हमारी औद्योगिक नीति के चलते हमारे यहां कागज का संकट बढ़ा है। कागज केवल एक उद्योग नहीं है बल्कि साबुन की तरह, तेल की तरह एक आवश्यक चीज है। हमारी बुद्धि के लिए, हमारी जानकारी के लिए, हमारे बच्चों के दिमाग के लिए, उनके विकास के लिए, हमारे देश में जो लोग विद्वान हुआ करते हैं वे अपनी बातों को अभिव्यक्त कर सकें कलम के जरिए, उन सारे कलमजीवियों के लिए, बुद्धिजीवियों के लिए यह एक आवश्यक वस्तु है। यह सही है कि बाहर से जो कागज आयेगा उस पर शुल्क में कमी करने की घोषणा की है लेकिन इतनी हिम्मत नहीं है कि बिल्कुल शुल्क से स्वतंत्र कर दिया जाए। अगर कागज को शुल्क से फ्री कर दें और चाहे जितना कागज मंगा लें तब तो शायद इस संकट का मुकाबला कर सकते हैं। इस बात के लिए पब्लिशर्स को और न्यूज प्रिंट के जो अखबार छापने वाले हैं उन लोगों को छूट दी जाए पूरी तरह, क्या सरकार इस पर विचार करेगी? तीसरी बात यह है क्या सरकार आवश्यक वस्तु कानून के तहत कागज को शामिल करेगी और जहां कहीं भी कागज का उत्पादन करने वाले कारखानेदार हैं अगर वे कानून को तोड़ कर मुनाफाखोरी की प्रवृत्ति दिखायेंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के बारे में देश के सामने कोई आश्वासन देगी ताकि देश की आम जनता जो ज्ञान और विकास के मामले में इस समय दहशत और अंधकार का माहौल महसूस कर रही है कागज की कमी के कारण उनको कुछ राहत मिल सके? क्योंकि स्कूल में पढ़ने वाले बड़े लोगों के बच्चे तो 50 रुपए, 100 रुपए, 150 रुपए की किताबें खरीद सकते हैं लेकिन गरीब आदमी के बच्चों के लिए अब स्कूल में और युनिवर्सिटी में पढ़ना कागज की महंगाई के कारण एक विलासिता बन गई है। क्योंकि सरकार ने अपनी नीतियों के चलते यह स्थिति पैदा की है। इसलिए इसका स्पष्टीकरण मैं मंत्री जी से चाहूंगा।

SHRI NILOTPAL BASU (West Bengal): Madam, I am afraid that the statement which has been given in reply to the Calling-Attention motion betrays an ignorance about the paper industry as such. There have been a lot of self-laudatory remarks about the performance of the paper industry.

Those who have studied the industry are well aware of the fact that

it is a 100-year old industry but, so far as the objectives of the industry are concerned, the major problem is that the total output of the industry in this country is much less than the demand. But there is no mention about that. There is only a mention about how the production is increasing. But the point which is important and relevant to this discussion is, how the production is increasing and whether it is keeping pace with the increase in the requirements of paper. I think the Government, while replying to this debate, must come out with a clear statement because one of the projections made by one very important study—the ICICI study of 1992—was that there was a clear increase in the gap between the demand and supply in the indigenous paper industry. So, what is the projection for this year, what is the projection for the next year, at the end of the Eighth Five-Year Plan, and what will be the gap between the demand and supply in the industry at the turn of the century?

Now, the difficulty with the paper industry is also this, that apart from a very small output, the capacity utilization of the paper industry is also very small. From as high as 90 per cent capacity utilization in the indigenous paper industry in 1965-66, it has not come down to only 60 per cent. Why this loss in capacity utilization? Those issues also have not been dealt with in the statement. One of the reasons pointed out by Shri Gurudas Das Gupta was a number of paper mills becoming sick. I don't know whether the industry Ministry has worked out any revival package so that these sick mills can be reopened so that a part of the capacity utilization can be revitalized.

The second point which arise is this, that this sickness is essentially due to the distortion that is there in the production pattern of the paper industry in this country. Now, the world over there are three basic resources which are being used for the production of paper. One is wood, the second is agricultural residues, and the third is waste paper—raw materials for the paper industry. But, because of the new environmental consciousness we are saying that so far as the wood-based paper industry is concerned, there is an increasing constraint on the raw material. So the world over there is a trend to switch over to agricultural residues and waste paper, but in our paper industry structure we find that more than 45 per cent of the total production is locked in such units which use wood as the basic raw material. So, has the Industry Ministry gone into this aspect—how to have a switchover from the thrust on wood-based paper production to waste-paper-based paper production?

1 p.m.

All those aspects have been left out.

The third aspect is technological obsolescence. There has been a sea-change in the technology the world over. Day in and day out we hear from the Government the great virtues of liberalisation and technological interface with foreign countries. I would like to ask of the industry Minister whether any specific memorandum of understanding has been signed with any foreign country to import any upgraded technology for improvement of the production process in the paper industry in the country. At least I am not aware of any particular effort geared towards upgrading the technology in the paper industry in the country, taking advantage of the so-called New Economic Policy which the Government talks about everyday.

Then, another issue is whether the Government is examining that so far as the production is concerned, inter-sectoral imbalances are emerging. There are basically two types of papers which are manufactured. One is the industrial paper, and the other is the cultural paper. We are seeing that there is a shift away from the cultural paper production to the industrial paper production. With the new blitzkrieg of consumerism and with the new revolution in the packaging industry, we are seeing that the older material which was used for packaging

is now being replaced by paper. So, there is a shift away from the cultural paper to the industrial paper, thereby aggravating the problem of paper to be made available in the areas of newspaper production, educational materials and so on and so forth. I do not know whether the Government is aware of such a sectoral deformity which is emerging in the paper industry in the country.

Finally, I would like to ask a couple of questions about the whole aspect of prices. I think, the statement gives enough material for attracting a privilege notice. I completely agree with Gurudas Das Guptaji that the increase that has taken place in the last four months has nothing to do with the input cost. There is no appreciable change in the inputs mentioned in the statement. This is enough to attract a privilege notice for misleading the House. There has been no appreciable increase in the excise duty. Why has it increased? The Minister has derived satisfaction from the fact that the newspaper production has gone up, that the newsprint production has gone up and that the imported newsprint accounts for only 2 per cent of the country's total requirement. But, the fact is that the present price hike is absolutely in sympathy with the increase in the price in the international market. In four months, on an average, the price has increased between Us $ 500 and US $ 550 per tonne. That is the increase in the price. It is more than 100 per cent.

How could it have happened? When the paper trade was liberalised in 1992, slowly and gradually the STC went out of operation. To have initial access to the Indian market, we found that there was a drop of about Rs. 2,000 in the...

THE DEPUTY CHAIRMAN: Let some time be left for the Minister to reply to all the questions.

SHRI NILOTPAL BASU: Just two minutes. I think, you would not need to ring the bell once more.

These are relevant questions. I think that the whole House will be enlightened by the reply of the Minister.

THE DEPUTY CHAIRMAN: There should be some relevant answer. For that, time is needed.

SHRI NILOTPAL BASU: So, Rs. 2,000 was the drop in the price in the international market, but after that once the access was gained and the entire consumer in the Indian market went towards imports, we saw that very rapidly the international price increased. Not only that; how does dependence on imports affect us? The major paper traders are based in Singapore and Honkong.

They saw to it that not a single ship transporting paper came to the Indian ports between October 1994 and February 1995. Because of that and because of the inefficient indigenous industry the prices of paper in the Indian market soared as if they had nothing to do with the input costs. So, I would say that the explanation given in the statement is totally inadequate and is totally unacceptable. It is one more exercise to hoodwink the people and to bluff the Parliament. The point is that certain concrete measures have to be taken. First, there has to be subsidy for small and medium newspapers.

THE DEPUTY CHAIRMAN: That point has been raised. So, please sit down. I want some time for the Minister to anwer. Please sit down. I have to give some time to the Minister. A lot of very relevant questions you all have asked. Let her have time to answer, because, as I said, at 2.30 we are going to have the Motion of Thanks on the President's Address.

SHRI NILOTPAL BASU: Finally, this exercise could have taken place even without the strike call. I do not know why the Government has undertaken this exercise only after the newspapers announced that they will go for a strike. Why the Government every time has to go for a fire-fighting?

THE DEPUTY CHAIRMAN: Even the Parliament gets agitated when the news comes in the papers. So, newspapers are relevant. Children have no platform to shout that their exercise books are expensive. Only when newspapers give a threat we also get conscious. Nobody raised this issue till newspapers threatened to go on a strike. (*Interruptions*)

SHRI SATISH AGARWAL (Rajasthan): We raised this issue for school going children. (*Interruptions*)

श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी (उत्तर प्रदेश) : उपसभापति महोदया, कई वरिष्ठ सदस्यों ने इस महत्वपूर्ण सवाल पर...

उपसभापति : सवाल ही पूछिएगा।

श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी : सवाल ही मैं पूछ रहा हूं। जितनी भी उसकी संख्या है और कीमतों की वृद्धि किस प्रकार हो रही है, मुनाफा खोरी किस प्रकार हो रही है उस संबंध में बहुत कुछ कह दिया है। लेकिन जो असाधारण मूल्य वृद्धि हो रही है वह बहुत चिंताजनक है और उसी विषय में मैं तीन-चार व्यवहारिक प्रश्न पूछना चाहता हूं। प्रथम तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जो पृष्ठ 1 के ऊपर पैरा दो में है—

> "The country is self-sufficient as far as the common variety of paper is concerned."

यह कामन वैरायटी का पेपर कौन है, पैकिंग पेपर है या हमारी बच्चों की किताबों और एक्सरसाइज बुक्स का है जिसके बारे में हमारे जनेश्वर मिश्र जी ने कहा था क्या है, या और किसी इस्तेमाल का पेपर है? अगर यह साधारण पेपर है तो मैं समझता हूं कि आवश्यकता सबसे अधिक यह है कि बच्चों की शिक्षा किस प्रकार से हो उनको कागज किस प्रकार से मिले। दूसरा, महोदया मेरा प्रश्न यह है जिसका संकेत आज भी और परसों भी जनेश्वरजी ने दिया वह यह है कि इस समय आप इसके निर्यात को क्यों नहीं बन्द कर सकते हैं? जब आलू और प्याज के निर्यात से कठिनाई होती है तो इसका निर्यात, एक्सपोर्ट क्यों नहीं आप कुछ समय के लिए बन्द कर सकते हैं जब तक कि हमारी जरूरतें न पूरी हो जाएं, और आयात में अधिक छूटें दें, इसके विवरण में नहीं जाना चाहता हूं जो कह दिया गया है। यह आयात का कागज क्यों नहीं और अधिक मंगाया जा सकता है? तीसरा प्रश्न महोदया जो मैं करना चाहता हूं वह यह है कि यह जो पेज 3 पर लिखा गया है, यह कहा गया है—

> "The Government is aware of the difficulties being faced in printing of textbooks and notebooks and is doing the needful to remove them."

वह नीडफुल है क्या? ये मंत्री महोदया, स्वयं एच.आर.डी. मिनिस्ट्री में रह चुकी हैं और ये जानती हैं कि बुक फेयर्स और जो हमारे नेताओं मौलाना आजाद ने, नेहरू ने, डा. राधाकृष्णन ने अकेदमीज कायम की, उनसे भी जो किताबें छप रही हैं वे भी 15–20 गुना कीमतों पर हमारे सामने आती हैं जो कि असाधारण हैं। जो कि बुक्स आफ मिलियन्स का जिसके ऊपर टाइटल हैं उनकी कीमत अब 35 रुपए और 36 रुपए हो रही हैं, तो यह बताने की चेष्टा करेंगी कि किस प्रकार से यह उसके लिए व्यवस्था करना चाहती हैं, जो हमारे पूजनीय नेता पहले करना चाहते थे? महोदया, एक चीज शायद आप को पता नहीं होगी, क्षमा करें अगर पता हो, मैं आपके ध्यान में यह लाना चाहता हूं जो मुनाफाखोरी का जिक्र किया गया उसके बहुत से पहलू हैं, मैं अभी नहीं कहना चाहता, लेकिन जो कागज आता है, कोरा कागज के ऊपर तो बैंक से लोन मिलता है, अगर पब्लिशर 20 लाख की किताबें छापता है या बुकसेलर किताबें रखता है तो उसके ऊपर बैंक लोन भी नहीं देता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि जब किताबें एक्सपोर्ट हो रही थीं इस देश से तो हमारा 11वां या 12वां नाम बुक पब्लिशिंग इंडस्ट्री में था और आज वह 17वां 18वां हो गया है, तो क्यों नहीं हम कागज के निर्यात करने की जगह किताबों के निर्यात करने की व्यवस्था करें और उस रूप से आप फारेन एक्सचेंज का पैसा इस देश में लाएं?

अंत में मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि कोरे कागज के ऊपर तो बैंक से आप लोन ले सकते हैं, लेकिन 20 लाख की किताबें जो पब्लिशर के यहां हैं या बुकसेलर के यहां हैं तो उसके ऊपर लोन नहीं मिलता है, तो क्या ऐसी कुछ व्यवस्था हो सकती है कि उनको भी आप सहायता करें ताकि किताबें कम कीमत पर लोगों को मिल सकें ? यह 500 रुपए की हिन्दी की पुस्तकें, 500–700 रुपए की किताबें हिन्दी की इस समय मिल रही हैं, जितनी भी मैगजीन्ज हिन्दी की हैं वे सब समाप्तप्राय हैं। स्कूल और कॉलेज के लड़के अपनी मैगज़ीन नहीं निकाल पा रहे हैं और अब यह आंकलन आखिर लाज्जुब की चीज़ है उपसभापति महोदया, कि आपने जो कांफ्रेंस की थी उसमें भी यह कहा गया था कि अगली सदी में इस देश में सब से ज्यादा बिना पढ़े-लिखे होंगे। यह तो आंकलन हो गया है एजुकेशन मिनिस्ट्री में, एच.आर.डी. मिनिस्ट्री में भी लेकिन कागज की आवश्यकता के आंकलन की बच्चों की आवश्यकता टैक्स्ट बुक्स की क्या है, एक्सारसाइज़ बुक्स की क्या हैं, वह अभी तक हो रहा है। आगे इसी में आप देखेंगे कि जो आंकड़े दिए गए हैं मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता, 350 मिलें 38 लाख टन कैपेसिटी की हैं वे अब 60 लाख टन होंगी।

"Expected to be created soon."

दोनों शब्दों के मतलब हम सरकारी भाषा में जानते हैं उसी तरह से और मजे की चीज़ है... (**व्यवधान**)

उपसभापति : आप ज्यादा जानते हैं।

श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी : मैं तो पुराना पापी भी हूं और आज भी हूं, क्योंकि आज भी बच्चे मांगते हैं कि आप पुरानी डायरी दे दीजिए। नौकरानी जो काम करती है उसके बच्चे कहते हैं। पूछता हूं कि यह डायरी से तुम्हें क्या करना है तो कहते हैं कि उस पर गणित करेंगे। पुरानी डायरी सन् 1994 की डायरी आपके यहां किस काम आएगी। यह स्थिति इस समय हो रही है।

उपसभापति। थैंक यू।

श्री त्रिलोकी नाथ मालवीय: एक बात कह कर मैं समाप्त करूंगा।

उपसभापति : अभी टाईम बिल्कुल नहीं है।

SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI: Twenty lakh tonnes is expected to be created on the basis.

वह भी क्रिएटेड और आन द बेसिस किस के ऊपर

of the IEMs filed and the LOIs issued?

मैडम, इससे आप समझ सकते हैं कि जो हमारे वरिष्ठ सांसद हैं इन्होंने जो मांग की है कि आप एक एक्शन प्लान तुरंत बताइए कि महीने भर में, दो महीने में, तीन महीने में आप इस देश की कागज की कमी की समस्या का निराकरण क्या करना चाहते हैं, उसके ऊपर ध्यान दिया जाए, वरना इस प्रकार का हमको लालीपॉप देने से हमको कोई फायदा नहीं है। बच्चों को वह मंजूर नहीं है। धन्यवाद।

उपसभापति। श्री जिचकर। बस दो सवाल पूछ लें।

DR. SHRIKANT RAMCHANDRA JICHKAR (Maharashtra): Respected Madam, a number of hon. Members have pointed out that the cost of input has nothing to do with the price rise. Will the hon. Minister ask the Bureau of Industrial Costs and Prices of the Government of India to declare the per Kg cost of production of newsprint produced by the various mills as well as the standard cost? This is my first question.

My second point is, a number of mills have entered into long-standing contracts with the State Governments for supply of bamboos and forest wood. For example, Ballarpur Paper Mills which is located in Chandrapur District has a long-standing contract with the Government of Maharashtra for the supply of bamboo. The bamboo which is costing Rs. 40

for the poor basket-maker is sold to the Ballarpur Paper Industry for four naye paise!

In spite of this fact, the Ballarpur Paper industries have increased their paper prices (*Interruptions*). Would the Government come out with a White Paper on all these long-standing contracts? (*Interruptions*). Thank you.

उपसभापति : मंत्री जी, जवाब दीजिए।

श्रीमती सरला माहेश्वरी (पश्चिमी बंगाल) : मैडम, मेरा सवाल भी जुड़ जाता?

उपसभापति : नहीं, जबाव देने दीजिए। इतने सवाल हो गए हैं, उनके तो जबाव आ जाएं, पहले फिर उसके बाद दोबारा पूछ लेंगे क्योंकि बहुत बहुत सवाल हो गये हैं।

श्रीमती कृष्णा साही : उपसभापति महोदया, माननीय सदस्य माथुर साहब एवं अन्य सभी माननीय सदस्यों ने कागज के दामों में हुई बढ़ोत्तरी पर चिन्ता व्यक्त की है। मैंने पहले भी कहा है और अभी भी कह रही हूँ कि आप लोगों के साथ ही इस गंभीर समस्या के समाधान के लिए मैं और सरकार गंभीर रूप से सोच रही है। आपकी चिन्ता के साथ मेरी चिन्ता भी जुड़ी हुई है।

उपसभापति महोदया, प्रकाशन और छपाई उद्योग जोकि सर्वसाधारण की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, वास्तव में यह चिन्ता का विषय है कि वह देश के लोगों को उपलब्ध न हो सके। तो इस पर हमें सोचना है। महोदया, आज के विचार विमर्श में जो भी मुद्दे उठाए गए हैं, उसमें बहुत महत्वपूर्ण बातें आप लोगों ने उठाई हैं और जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही गयी, वह यह है कि शिक्षा से संबंधित कागज के कुल उत्पादन का कुछ भाग निर्धारित किया जाये। जैसाकि मैंने यहां पहले भी कहा है कि कुछ उपाय सरकार के विचाराधीन है और शैक्षणिक क्षेत्र को और विशेष रूप से किताबों तथा कापियों की छपाई में कुछ राहत प्रदान करने के लिये हम सब प्रयत्न कर रहे हैं। हमने एच. आर. डी. मिनिस्ट्री को भी कहा है कि वह अपनी आवश्यकताओं को बतायें। इसके अतिरिक्त पेपर निर्माताओं से वार्ता कर पेपर मूल्य को कम रखने और उत्पादकता को बढ़ाने का प्रयास करने के लिये उन्हें प्रभावित किया जा रहा है। मैंने स्वयं मैनुफैक्चरर्स की बैठकें बुलाई हैं और उनसे बार-बार इस बारे में आग्रह किया है कि वह इस पर ध्यान दें। कागज का मूल्य ...(**व्यवधान**)...

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : इसका असर क्या हुआ?

श्रीमती कृष्णा साही : कागज के मूल्य में वृद्धि मुख्यतः कोयला, कास्टिक सोडा और अन्य कच्ची सामग्री जैसी आवश्यक इनपुट्स की लागत में समग्र वृद्धि के कारण हुई है। हाल में आयातित पल्प और वैस्ट - पेपर की लागत कई गुना बढ़ गई है।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : आप कागज देख लीजिये, शायद वही तो नहीं पढ़ रही हैं, जोकि पहले वक्तव्य दे चुकी है?

श्रीमती कृष्णा साही : माथुर साहब, हमने हाथ से सभी पांइट्स को लिखा है ...(**व्यवधान**)... यह मैंने पहले पढ़ा है और अब इससे आपको जबाब दे रही हूं।

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: That is not point. (*Interruptions*). Madam, after all, you are reading from a paper. (*Interruptions*). That is it.

श्रीमती कृष्णा साही : आप आंकड़ा जानना चाहेंगे, तो वह मैं कैसे बिना देखे बता सकती हूं? ...(**व्यवधान**)...

उपसभापति : आप एक मिनिट बैठिए आप भी जरा बैठिए । मंत्री जी, जो आपने अपना वक्तव्य माननीय माथुर जी के कालिंग अटेंशन पर पढ़ा था, मुझे यकीन है कि उसकी गंभीरता को आप समझती हैं और सरकार भी समझती हैं, मगर उसको पढ़कर उससे जुड़े हुए कुछ सवालात जो यहां उठाए गये हैं, उनका जबाब आप दे । तो वह पूछ रहे हैं कि आपने क्या कदम उठाए हैं ? आप क्या कदम उठा रही हैं या सरकार के विचाराधीन हैं? पर सरकार क्या विचार कर रही हैं, यह वे मालूम करना चाहते हैं, ताकि उनको और तसल्ली हो जाये, क्योंकि अगर हम यह इन्तजाम करेंगे कि "पेड़ बड़े होंगे तब तो बीस साल लगेंगे।"

श्री गुरूदास दास गुप्त : मैडम, मेरा एक और सवाल है। मंत्री जी जैसा बोल रही हैं कि रा-मैटेरियल के दाम बढ़ने के कारण कागज का दाम बढ़ता जा रहा है, हम लोग बतला रहे हैं कि .. ...**(व्यवधान)**...

उपसभापति : उन्हें बोलने दें। आप उन्हें बोलने नहीं देते हैं, गुरुदास दास गुप्त। बोलिए, मंत्री जी।

Let her speak. Otherwise, I will adjourn the House for lunch.

श्रीमती कृष्णा साही : उपसभापति महोदया, पेपर पर कोई भी स्टेचुटरि प्राइस कंट्रोल हमारा नहीं है, यह बात तो मैंने कही ही है और इनपुट कोस्ट जो है उसका भी परसेंटेज अगर आप कहेंगे तो मैं बताऊंगी, नहीं तो ऐसे बता रही हूं कि सरकार एक पैकेज पर विचार कर रही है । मैंने कहा, मैं आपको आश्वासन देना चाहती हूं ...**(व्यवधान)**...

उपसभापति : पैकेज के बारे में पूछ रहे हैं क्या ?

श्रीमती कृष्णा साही : पहले उन्होंने कहा था कि सरकार कोई एक्शन प्लान बना रही है या नहीं ?

श्रीमती सरला महेश्वरी : कोई लोंग टर्म प्लानिंग है या नहीं ?

श्रीमती कृष्णा साही : उपसभापति महोदया, इसमें कई विभाग संबंधित हैं, एच.आर.डी. संबंधित हैं, कामर्स संबंधित है, इंडस्ट्री संबंधित है । जैसा मैं बता रही हूं कि हमारा नियंत्रण जो है पेपर का, स्टेचुटरि नियंत्रण इसमें नहीं है। यह स्टेचुटरि प्राइस कंट्रोल के अंदर नहीं आता है, लेकिन सरकार इसके ऊपर देख रही है । कल ही एक एलान हुआ, जिससे कि काफी राहत हुई । ...**(व्यवधान)**... :

उपसभापति : एक मिनट । आर्डर प्लीज, आर्डर ।

श्रीमती कृष्णा साही : कल भी एक एलान हुआ । सरकार ने बताया यह न्यूजप्रिंट के बारे में, उससे राहत काफी मिलेगी और उससे प्रभाव पड़ेगा इसके ऊपर ।...**(व्यवधान)**...

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : बच्चों का क्या होगा ? ...**(व्यवधान)**...

उपसभापति : देखिये, मंत्री जी, ऐसा है कि अभी जिचकर जी बोलकर गये, जो बांस 40/- रुपये किलो मिल रहा है बाहर, वह 4 पैसे किलो दिया जाता है पेपर मिल को, बलारपुर पेपर मिल को, तो कहां बढ़ोतरी हुई ? जबकि और सदस्यों ने और जगेश देसाई जी ने बताया कि ऐसी चीजों की कीमतों में इतनी बढ़ोतरी नहीं हुई, जितनी पेपर में हुई । पेपर की समस्या को लेकर ही आज आपको यहां बुलाया है । कुछ थोड़ा तो बता दीजिये कि क्या हो रहा है ?

श्रीमती कृष्णा साही : उपसभापति महोदया, वही मैं कहना चाहती हूं कि कोस्ट आफ इनपुट में बढ़ोतरी है । जरा मुझे आप परसेंटेज तो बताने दीजिये ताकि पता चले कि क्यों बढ़ा है? ...**(व्यवधान)**...

श्री के. आर. मलकानी (दिल्ली) : क्यों बढ़ा है ? यह किसकी जिम्मेदारी है ? यह तो सरकार की जिम्मेदारी है ? ...**(व्यवधान)**...

श्रीमती कृष्णा साही : : रा-मेटेरियल के इनपुट में परसेंटेज इंक्रीज तो सुन लीजिए । . . . (**व्यवधान**) . . .

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : आप साफ-साफ बताइये कि आप क्या करने वाले है ? जो कारखानेदारों और उनकी मांगें हैं, उसके बारे में आपने क्या किया है ? आप यह बता दीजिये कि उनकी जो मांग है, उसमें यह यह हम करना चाहते हैं, यह यह नहीं करना चाहते हैं । . . . (**व्यवधान**) . . .

श्रीमती कृष्णा साही : मैं सिर्फ एक ही बात कह रही हूं कि प्राइस का स्टेचुटरि कंट्रोल हमारा नहीं है । मैंने मैनुफेक्चरर्स को बुलाकर उनसे आग्रह किया है, निवेदन किया है कि आप यह जो प्राइस राइज हुआ है इसके ऊपर मनन चिंतन कर जरा देखिये । . . (**व्यवधान**) . . जो आपने कहा वह मैंने बताया । . . . (**व्यवधान**) . . .

उपसभापति : आप बोलने दीजिये मंत्री जी को प्लीज । आप लोग बात करने दीजिये मंत्री जी को . . . (**व्यवधान**) . . . देखिये दस मिनट रह गये है बल्कि दस से भी कम रह गये हैं आप इनको बोलने दीजिये ।

श्रीमती कृष्णा साही : उपसभापति महोदया, दो-तीन सवाल इन्होंने उठाये, जिनमें एक इंपोर्ट ड्यूटी का था कि यह 90 प्रतिशत है, तो मैं यह कहना चाहती हूं कि विभिन्न प्रकार के पेपर पर भिन्न-भिन्न इंपोर्ट ड्यूटी हैं परन्तु किसी भी प्रकार के पेपर पर 40 प्रतिशत से अधिक ड्यूटी नहीं है । अभी इसे 65 से घटाकर 40 कर दिया गया है । . . . (**व्यवधान**) . . .

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : यह तो पहले वाले स्टेटमेंट मे बताया ही गया है । . . . (**व्यवधान**) . . .

SHRI K. R. MALKANI: It must be abolished and not reduced. Abolish it completely. (*Interruptions*)

श्रीमती कृष्णा साही : उपसभापति महोदया मैं कहना चाहती हूं कि सरकार इस पर विचार कर रही है । मैनुफेक्चरर्स को बुलाकर हम लोगों ने बातचीत की है और एक पैकेज तैयार कर रहे हैं, जिससे कि एजुकेशनल सेक्टर में भी राहत मिले, आम लोगों को भी कुछ राहत मिले । जब यही जानना चाहते है तो मैं अभी इस स्थिति में नहीं हूं कि मैं एक बार में तत्काल ही कर दूं लेकिन सरकार इसमें तीन बार बात कर चुकी है और आगे भी बात करती जा रही है । . . . (**व्यवधान**) . . .

SHRI NILOTPAL BASU: What is the use of having a debate like this when she is not prepared to answer the various points raised by us?

श्रीमती कृष्णा साही : मैडम, मैंने तो तैयारी की है, सभी प्वाइंट्स जो माननीय सदस्यों ने उठाये हैं, सभी प्वाइंट्स को हमने नोट किया है लेकिन हमको उत्तर ही नहीं देने दिया जा रहा है ।

SHRI MD. SALIM: Madam, please ask her to give pointed answers.

उपसभापति : आप बैठिये न मिस्टर सलीम । प्लीज सिट डाउन । . . (**व्यवधान**) . .

श्री महेश्वर सिंह (हिमाचल प्रदेश) : मंत्री जी बार-बार हमें बोलने के लिये प्रेरित कर रही हैं तो क्या करें?

श्रीमती कृष्णा साही : सिक यूनिट्स की बात है तो उसके लिये सरकार ने बी०आई०एफ०आर० का गठन किया है । "सिनार मास" जो अभी एक विदेशी मिल लगाने जा रही है, उसमें हम बढोतरी करने जा रहे हैं । जो इन्होंने कहा कि प्रोडक्शन के लिये क्या करना चाहिये, वह मैं बता रही थी कि जो हमारी नई तकनीक है उसका हम उसमें इस्तेमाल करने जा रहे हैं और जहां तक जो कुल उत्पादन है हमारा, यहां पर 'एक्सपोर्ट को बेन' करने के लिये कहा गया है । तो यह एकाएक हम

इसलिये नहीं कर सकते क्योंकि अगर एक्सपोर्ट हम बेन करना चाहते हैं तो उस पर विचार होगा, कामर्स मिनिस्ट्री से भी बातचीत करनी होगी, एक्सपोर्ट-इंपोर्ट का यहां तक सवाल उठता हैं। तो अल्टरनेटिव के रूप में कुछ न कुछ हमें सोचना पड़ेगा और हम इसमें सोच रहें हैं। निर्यात का विकल्प हम अगर अचानक ही वापिस ले लेते हैं तो इससे केवल उद्योग पर ही बुरा असर नहीं पड़ेगा बल्कि यह उद्यमियों के लिये भी अनुचित होगा। इसलिये सरकार सोच-समझकर ...(व्यवधान)...

उपसभापति: अगर ओ०जी० एल०में लगायेंगे तो फारेन एक्सचेंज तो जाएगा ही जाएगा।

श्रीमती सरला माहेश्वरी: ओ०जी० एल० का क्या प्रभाव पड़ेगा?..(व्यवधान).. मैडम, जो कल घोषणा की गई, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा?

श्रीमती कृष्णा साही: मात्र 2 परसेंट हम निर्यात करते हैं? बाहर को जो हम अभी निर्यात करते हैं, 2 परसेंट निर्यात करते हैं, जैसे कि आर्ट पेपर है या चेक पेपर हुआ, बाकी तो नहीं किया जाता है। यह तो मैंने पहले ही बताया है कि कुल निर्यात का ...(व्यवधान)...

श्री जगदीश प्रसाद माथुर: आप निर्यात करते हैं या आयात करते हैं? निर्यात को आयात, आयात को निर्यात।

उपसभापति: बोलने तो दो। (व्यवधान) आप एक मिनट जरा खामोश रहेंगे। आप लोग बोलने नहीं देते। बोलिये। Let her speak.

श्रीमती कृष्णा साही: उत्पादन का मात्र 2 प्रतिशत ही निर्यात किया जाता हैं। ...(व्यवधान)...

उपसभापति: आप एक मिनट जरा खामोश रहेंगे? मुझे सुनने दीजिये।

श्रीमती कृष्णा साही: उपसभापति महोदया, कुल उत्पादन जो है वह 22 लाख टन से अधिक है और कुल निर्यात मात्र 50 हजार टन है, तो मैं इसमें क्या गलत कह रही हूं आप जो बता रहे हैं मुझे? अब जैसे आपने बताया, आपने जो बताये वे प्वाइंटस मैंने नोट किये हैं कि पेपर इंडस्ट्री कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है। अभी हमारे सामने जो पुरानी मशीनें हैं उनको रिप्लेस करने में थोड़ी कठिनाई है लेकिन हम फ्रेंज्ड मैनर में उनको रिप्लेस कर रहे हैं, बड़े पैमाने पर यह अभी संभव नहीं हो पा रहा है, जो माडर्न टैक्नोलोजी की बात उन्होंने कही है। इसके साथ ही साथ अनेक मिल्स में, पुरानी टैक्नोलॉजी के कारण, रॉ-मेटेरियल की कमी के कारण, पावर और कोयला की शार्टेज के कारण, हमें उपलब्धि कम हो रही है और "कैपिसिटी यूटिलाइजेशन" में थोड़ी कमी आई हैं लेकिन मैंने जैसा कहा है कि सरकार इसके ऊपर पैकेज प्रोग्राम सोच रही है कि कैसे लोगों को पेपर हम सस्ते दामों पर उपलब्ध करायें। वर्तमान जो डिमांड है, जिसकी चर्चा हमने की है 22 लाख टन है और उत्पादन भी उतना ही है और पांच साल के बाद जो डिमांड हैं वह 32 लाख टन होगा। प्रत्येक वर्ष करीब 10 प्रतिशत मांग में वृद्धि होती है, पांच साल के बाद उत्पादन क्षमता में करीब 60 लाख टन की और वृद्धि होगी। विदेशी तकनीक तो आ ही रही है, हम सभी लोग जानते हैं। "सिनारबास" जिसकी मैंने चर्चा की है कि वह बड़ी विदेशी कम्पनी है जो लेटेस्ट टैक्नोलॉजी लेकर एक बड़े उद्योग को लगाने जा रही है। साथ ही "सहारनपुर" के बारे में मैंने कहा है कि उनमें "मोस्ट माडर्न टैक्नोलोजी" उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है ताकि वहां से नई तकनीक हमें मिल सके।

आपने कहा कि बिल्कुल व्यर्थ है, आंकड़े नहीं बताने के लिये कि कितना राइज हुआ है रॉ मैटेरियल के इन-पुटस में, कितना परसेंटेज राइज हुआ है, उसी प्रकार हम इंटरनेशनल प्राइस प्रति टन

में कितना इंक्रीज हुआ है और पल्प जिसको लांग फाइबर्स कहते हैं में क्या वृद्धि हुई है। एक पीरियड में बता सकते हैं कि अप्रैल, 1994 से जनवरी, 1995 तक, सही आपने कहा कि यू.एस. डॉलर 380 से यू.एस. डालर1200, परसेंटेज इंक्रीज 215 प्रतिशत हुआ है। इंक्रीज इन इन्टरनेशनल प्राइस आफ बेस्ट पेपर, डबल सॉरटिड जिसको आप बताते हैं, अप्रैल, 1994 से जनवरी, 1995 तक यू.एस. डॉलर 17 से यू.एस. डॉलर 300, इंक्रीज हुआ 1665 प्रतिशत। इंक्रीज इन पेपर प्राइस, में तो खुद ही बता रही हूं आपको कि यह जो राइज हुआ है, कोयला में 13 प्रतिशत का राइज हुआ है, कॉस्टिक सोडा में 110 प्रतिशत, इलेक्ट्रिसिटी में 25 प्रतिशत राइज हुआ है। तो इतने जो इनपुट के कॉस्ट्स बढ़े हैं, उसके कारण हम लोगों को थोड़ा देखना पड़ेगा। (व्यवधान)

उपसभापति: इससे पहले यहां एक मंत्री..मंत्री जी, आप बैठें। अभी हम लोगों को एड्जॉर्न करना है। यहां सवाल उठा है। हो सकता है आपके पास उसके जवाब अभी मौजूद नहीं हों मगर अभी तो हाउस हमारा चल रहा है, काफी दिन चलेगा क्योंकि इस समस्या का समाधान तो करना ही है। अभी ऐक्जाम हो गए हैं, परीक्षाएं हो गई हैं, स्कूल खुलेंगे, बच्चों को किताबों की जरूरत पड़ेगी तो उनको ऐक्सरसाइज़ बुक देनी हैं, न्यूज़पेपर की समस्या का थोड़ा समाधान हुआ है। करीब-करीब जो-जो सवालात किए गए हैं, आप उनके बारे में मालूमात करके हाउस को उसके बारे में जानकारी दे दीजिए और इस के अलावा जो कॉस्ट एण्ड एकाउंट्स की कमेटी है, उसके अंदर आप यह भी मालूमात करिए कि कितना कॉस्टिक सोडा लगता है? 180 प्रतिशत वृद्धि हुई है, 140 प्रतिशत वृद्धि हुई तो उससे प्रोडक्शन पर कितने परसेंट अफेक्ट पड़ेगा? क्या वह रेशियो में है इनक्रीज के या नहीं है? जो ब्लेज्ड पेपर की कॉस्ट बढ़ी है, वह इनक्रीज के रेशियो में है या नहीं है क्योंकि अगर रेलवे के फेयर बढ़े हैं तो वह रेशियो में बढ़े हैं या नहीं बढ़े हैं कॉस्ट के? क्योंकि जो फायदा उठाना चाहते हैं, मुनाफा करना चाहते हैं, वे लोग तो अगर आप एक पैसा बढ़ाएंगे तो वे एक रुपया बढ़ा देते हैं तो इसलिए आपको इस पर कुछ सोचना पड़ेगा। तो यह बात आप मालूम करके बता दीजिए और दूसरे, जब नीति चेंज हो रही है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी चेंज हो रही है और आर्थिक नीति तो अगर हमारा कंट्रोल नहीं है जहां, जहां कंट्रोल है वहां हम लूज़ कर रहे हैं जहां कंट्रोल नहीं है तो वहां हम ला भी सकते हैं लोगों के हित के लिए और खास तौर पर जो हमारी शिक्षा के विषय में हुई है उसके लिए हम निरंतर उसके ऊपर कुछ लगा सकते हैं कंट्रोल तो इन-इन जगहों पर हम कंट्रोल लगाएंगे क्योंकि ये हमारा एक कमिटमेंट है कि हम बच्चों को सस्ती किताबें दें, न्यूज़पेपर द क्योंकि It is a right of information. It is a fundamental right.

श्री जनेश्वर मिश्र: मैडम, कॉलिंग अटेंशन का जवाब तो आपने ही दे दिया। ...(व्यवधान)...

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Madam, you are really moving the Calling Attention.

श्री जगदीश प्रसाद माथुर: ये सस्ता कागज़ देंगी क्या ?...(व्यवधान)...

उपसभापति: ये तो वे जबाब देंगी... तभी सस्ता कागज़ तो अलग बात है।... (व्यवधान)...सेशन खत्म होने से पहले ही जवाब दिला दूंगी। I will get the answers before the Session is over.

The House is adjourned for one hour for lunch.

The House then adjourned for lunch at thirty three minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at thirty-two minutes past two of the clock,

The Vice-Chairman (Miss Saroj Khaparde) in the Chair.

MOTION OF THANKS ON PRESIDENTS ADDRESS CONT, D

SHRI VAYALAR RAVI (Kerala): Madam, Vice-Chairperson, I was mentioning about the new tendencies that are developing concerning the Centre and the States. There is confrontation between the Centre and a few States leading to a Constitutional crists. Before I can elaborate on this point, I would like to point out one or two such instances.

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): Mr. Ravi, can you sit down for a minute? From your party there are nine Members who have yet to speak. I don't think I will be able to give more than eight to nine minutes to each speaker. So, please try to be brief so that everybody gets an opportunity.

SHRI VAYALAR RAVI: I shall be very brief. In Gujarat, as soon as the BJP came to power, because of some kind of pressure from the oil lobby, they seized and sealed the godowns of the The National Dairy Development Board. This is a Central Government institution. There is a proper forum and there is a proper way of doing this. Now, you are seizing and sealing all these godowns so that the oil lobby can loot the public.

SHRI SATISH AGARWAL (Rajasthan): This is not true.

SHRI VAYALAR RAVI: I may be wrong. But I believe it because the prices have gone up. Madam, the question is that if every State with a non-Congress Government starts seizing and sealing the FCI godowns, where will we land ourselves? There is a proper forum where this can be discussed. This amounts to a threat. This new trend that is developing is very disturbing. We have problems from the Southern parts of the country also. Madam, there are certain Constitutional heads like the Governor, the Chief Minister and the Speaker. Certain norms have to be followed because the Constitution that we are enjoying today is a product of the Indian revolution. I am sorry that my party lost in many States. I am sad about it. But this shows the inherent strength of our democratic system. It shows that the people have expressed their faith in the Indian Constitution and in democracy. They can defeat my party as they defeat the other parties. We appreciate that. But my question is, do the leaders of the political parties understand the sentiments of the poor people who voted them to power? What is happening in Tamil Nadu today? I do not want to go into the details. It is a piteous situation there. I am not defending the Governor. I may not agree with him. I have my own views on that. But if one person is wrong, it is not necessary that the others also should do the same thing. There should be co-existence of the Governor, Chief Minister and the Speaker. Unfortunately, there is more of confrontation than of co-existence. This has led to an unprecedented situation. The Legislature resorts to suspension of the rules. This House has some rules. And you can suspend the rules. But are we going to suspend the rules every day? I had an occasion to be in the Lok Sabha and I have the privilege to be here in this House. The Chair may throw out some Members of this House. We understand that. But we discuss and decide about it. But there is a Legislature in this country which throws out every Opposition Member every day from the Assembly. It dismisses and suspends the leaders of the Opposition parties. We have not dismissed the leaders. I do not know what is happening there. Is it democracy? It is murdering democracy within the democracy, using democracy to murder democracy. This is what is happening in Tamil Nadu. I do not want to go into the details of that. I would only quote a few lines ffrom "*The Hindu*" which is one of the leading newspapers, an esteemed newspaper, in this country. I am not elaborating anything. I would only quote what has been said in an